Loss due to non-allotment of flats

225. SHRI RAJNI RANJAN SAHU: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that several crores of rupees invested in flats purchased by the Directorate of Estates from DDA remained blocked for several years;

(a) if so, the reasons therefor; and

(b) what is the quantum of revenue loss and the number of the allottees who suffered as a result thereof?

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI DAULAT RAM SARAN): (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

उत्तर प्रदेश में खाद्यान्न उत्पादन

226. **श्री राम नरेश यादव :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश में खाद्यान्न उत्पादन को दुगना करने के लिए कोई कार्यक्रम तैयार किया है;

(ख) क्या राज्य सरकार ने उक्त लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्रीय सरकार से सहायता मांगी है ; और

(ग) यदि हां, तो उक्त कार्यक्रम के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश को कितनी सहायता दी जाएगी ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयन्तीलाल वीरचन्द, भाई शाह) : (क) जी नहीं । राज्य ने 1989-90 में हुए 33.7 मिलियन मीटरीटन खाद्यान्न उत्पादन को 1994-95 में 43.0 मिलियन मीटरीटन तक बढ़ाने का प्रस्ताव किया है ।

(ख) और (ग) राज्य में खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाने के लिए, समेकित चावल विकास कार्यक्रम, गेंहू, मक्का और कदन्न तथा दालों के लिए विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम , राष्ट्रीय दलहन विकास कार्यक्रम आदि जैसी कई योजनाऐं क्रियान्वित की जा रही हैं । मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित की जा रही योजनाओं के संबंध में उत्तर प्रदेश राज्य को दी जाने वाली सहायता की मात्रा का निर्धारण आठवीं पंचवर्षीय योजना के स्वीकृत हो जाने के पश्चात् किया जाएगा ।

उत्तर प्रदेश में दूध का उत्पादन

227. **श्री राम नरेश यादव :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में प्रति वर्ष दूध का कितना कितना उत्पादन हुआ है ;

(ख) किसानों से दूध किस दर पर खरीदा जाता है ;

(ग) गाजियाबाद तथा मेरठ से अन्य संस्थानों को कितनी कितनी मात्रा में दूध सप्लाई किया जाता है, तथा किस कीमत पर ;

(घ) क्या उपरोक्त दूध की कीमत के भुगतान में अधिक विलम्ब किया जाता है ; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयन्तीलाल वीरचन्दभाई शाह) : (क) विगत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में वर्षवार, अनुमानित वार्षिक दुग्ध उत्पादन निम्नवत् है :

वर्ष	अनुमानित दुग्ध उत्पादन
	हजार मीटरी टन में
1986-87	8417
1987-88	8595
1988-89 (अंतिम)	8824

(ख) माह अक्टूबर, 1990 के दौरान सरकारी डेरियों द्वारा अदा किया गया औसत उत्पादक मूल्य निम्नवत् है :—

(i) गाय का दूध—3.35 रुपये से 3.83 रुपए प्रति कि० ग्रा० (4% वसा तथा 8.5% ठोस बान्ड फ्रेट)

(2) भैंस का दूध–4.50 रुपए से 5.14 रु० प्रति० कि०ग्रा० (7% वसा तथा 9% ठोस नाट–फैट)

(ग) से (ङ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जाएगी ।

व्यापक फसल बीमा योजना को बढ़ावा दिया जाना

228. **श्री राम नरेश यादव :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार व्यापक फ़सल बीमा योजना के क्रियान्वयन में पाई गई कमियों के संदर्भ में ऋण संगठनों, साधारण बीमा निगम तथा "नाबार्ड" की भूमिका की समीक्षा करने का विचार रखती है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उक्त योजना को बढ़ावा देने के लिए क्या-क्या कदम उठाए गए हैं, उठाये जाने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयन्तीलाल वीरचन्द भाई शाह) : (क) से (ग) सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों और अन्य संबंधित एजेंसियों से जानकारी एकत्र करने तथा सातवीं योजनावधि के दौरान योजना को चलाने से प्राप्त किए गए अनुभव के आधार पर बृहत फ़सल बीमा योजना में कार्यविधि संबंधी परिवर्तन करने की दृष्टि से 23–5–90 को नई दिल्ली में फ़सल बीमा संबंधी एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई । कार्यशाला द्वारा दिए गए सुझावों में शामिल हैं :–नियमित आधार पर राज्य सरकारों द्वारा अपनी राज्य बीमा निधि को वित्तीय योगदान, ऐसी फ़सलों, जिन्हें विभिन्न ऋण अवधियों की आवश्यकता होती है, को छोड़कर बृहत फ़सल बीमा योजना के अंतर्गत निर्धारित मौसमी विशेषताओं को जारी, रखना ऋण वितरण एजेंसियों द्वारा भारतीय केंद्रीय बीमा निगम को समय पर अपनी घोषणाओं को प्रस्तुत करना, फ़सल कटाई मशीनरी में सुधार करना, सहकारी ऋण संस्थाओं, वाणिज्यक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की मूल्यांकन यांत्रिकी को सुदृढ़ करना, ऋण वितरण एजेंसियों द्वारा समय पर सामान्य ऋण सीमा विवरण तैयार करना, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार ही कृषि ऋणों का वितरण, ऋण वितरण एजेंसियों द्वारा समय पर अलग अलग किसानों के दावों की राशि जमा करना, जिला स्तरीय कार्य ढांचा आदि उपलब्ध करा कर बृहत फ़सल बीमा योजना के क्रियान्वयन में लगी एजेंसियों, के बीच उपयुक्त समन्वय स्थापित करना । इन सुझावों के आधार पर 26–11–90 को सरकार द्वारा सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को उपयुक्त मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए गए । इसको ध्यान में रखते हुए जहां तक बृहत फ़सल बीमा योजना का संबंध है, सरकार का ऋण संगठनों, साधारण बीमा निगम और नाबार्ड की भूमिका की समीक्षा करने का प्रस्ताव नहीं है ।

उत्तर प्रदेश में चावल के उत्पादन में वृद्धि के लिए प्रायोगिक परियोजनाएं प्रारंभ करना

229. **श्री राम नरेश यादव :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उत्तर प्रदेश में चावल का उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रायोगिक परियोजनायें प्रारंभ करने के लिए कुछ मंडलों/ब्लाकों का चयन करने का विचार रखती है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) चावल के उत्पादन के लिए केन्द्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश को कितनी वित्तीय सहायता दिये जाने की संभावना है ; और

(घ) इस परियोजना के प्रारंभ होने की संभावना है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयन्तीलाल वीरचन्दभाई शाह) : (क) से (घ) सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत चलाए गए "विशेष चावल विकास कार्यक्रम" की पूर्व तैयारी के रूप में